मसालों का उत्पादन और उनकी गुणवत्ता

855. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मसालों के उत्पादन व गुणवत्ता के मामले में कोई सुधार नहीं किया गया है ;

(ख) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभव पटल पर रख दी जायेगी।

आयात और निर्यातों का मूल्य

856. श्री राघवजी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान आयात किये गये और निर्यात किये गये माल का,वस्तु-वार और माह-वार, मूल्य रुपयों में कितना-कितना है; और

(ख) क्या यह सच है कि विदेशी व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इसे पक्ष में करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान आयात और निर्यात की गई वस्तुओं के, रुपये के रूप में, मदवार तथा माहवार मूल्य डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित क्रमश: मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड इन इंडिया"(1992-93 और 1993-94 के वार्षिक अंक)खंड ii-आयात तथा (मंथली स्टेटिस्स्टक्स आफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया") 1992-93 तथा 1993-94 के वार्षिक अंक), खंड-I-निर्यात तथा पुन: निर्यात में उपलब्ध हैं । इन खंडों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है । वर्ष 1994-95 की अवधि का प्रकाशन (वार्षिक अंक) अभी नहीं छपा है।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार ने नीतियों और क्रिया-विधियों को और अधिक निर्यात-अभिमुख बनाने हेतु अनेक उपाय किये हैं । इनके फलस्वरूप, निर्यातों में वर्ष 1993-94 में डालर के रूप में 20.4 और अप्रैल, 1994-जनवरी, 1995 के दौरान डालर के रूप में 17 से अधिक की वृद्धि दिखाई देती है । इन उपायों में ये शामिल हैं ; निर्यात लाभों पर आयकर में छूट, परिवर्तनीय मुद्रा में निर्दिष्ट सस्ते निर्यात ऋण की उपलब्धता ,निर्यात बाजार विकास के लिये निर्यात संवर्धन परिषदों को सहायता, देना, आदि ।

Misuse of value based advance Licencing Scheme

857. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government's attentioa has been drawn to the newsitem which appearsd in the Business Standard of 21st December, 1994 about fantastic profits made by Calcutta bnsed Gaitapati Exports Ltd. and if so whether the Value based advance licencing (VABAL) Scheme is being operated illegitimately and is likely to end up into another Steam:

(b) whether the nexus between his Ministry, DGFT and certain unscmpsulos exporters is intentianlly overlooking the hard realities of this scheme;

(c) whether operation of this scheme is resulting in huge revenue loss to the exchequer; and